भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4077

दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

'स्वामित्व' योजना

†**4077** डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण'स्वामित्व' योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का राज्यवार और विशेषकर महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिलों में ब्यौरा क्या है ;

(ख) 'स्वामित्व' योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक आवंटित की गई और व्यय की गई कुल निधि का महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत शामिल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों का महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है ;और

(घ) भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क), (ग) और(घ): 20 मार्च 2025 तक, महाराष्ट्र राज्य सहित स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की राज्यवार वर्तमान स्थिति अनुलग्नक 1 में संलग्न है। धुले और नासिक जिलों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की वर्तमान स्थितिअनुलग्नक 2 मैं दी गई है ।

(ख) इस योजना के तहत, ड्रोन के माध्यम से विस्तृत पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) करने तथा महाराष्ट्र सहित इस योजना को अपनाने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) स्थापित करने हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धनराशि प्रदान की जाती है। अब तक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

सीओआरएस के लिए	₹ 116.54 करोड़
एलएसएम के लिए	₹ 257.93 करोड़

राष्ट्रीय परियोजना निगरानी इकाई (एनपीएमयू), स्थानिक नियोजन एप्लिकेशन 'ग्राम मानचित्र' में वृद्धि करने, केंद्रीय अवसंरचना और अन्य तकनीकी और सॉफ्टवेयर जरूरतों में सहायता करने के लिए अब तक एनआईसी को (एनआईसी-सर्विसेज इंक के माध्यम से) ₹ 36 करोड़ की धनराशि भी जारी की गई है।

इसके अलावा, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों और राज्य परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि भी प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र सहित स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन हेतु आईईसी और एसपीएमयू के लिए राज्यों को अब तक जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 3** में संलग्न है।

***

अनुलग्नक 1

'स्वामित्व योजना' के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4077 के भाग (क), (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान और संपत्ति कार्ड का राज्य ण्र वर्व ि्र वेत्र क्ष ज्य्र ंघ स्/

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ड्रोन उड़ान वाले (गांव)	तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांव	तैयार किये गये संपत्ति कार्डों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	186	141	7,409
आंध्र प्रदेश *	13,321	0	0
अरुणाचल प्रदेश	3,465	0	0
असम	946	0	0
छत्तीसगढ़	15,791	1,202	70,307
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ^	80	75	4,397
दिल्ली	31	0	0
गोवा	410	410	6,72,646
गुजरात	14,101	7,562	12,70,417
हरियाणा	6,260	6,260	25,15,646
हिमाचल प्रदेश	13,882	238	5,395
जम्मू और कश्मीर	4,400	1,006	39,204
झारखंड	240	0	0
कर्नाटक	18,479	3,898	10,08,224
केरल	597	0	0
लद्दाख	230	148	15,623
लक्षद्वीप द्वीपसमूह	10	0	0

मध्य प्रदेश	43,014	33,929	39,94,343
महाराष्ट्र	37,609	17,013	26,76,971
मणिपुर	209	0	0
मिजोरम	319	27	2,909
ओडिशा	2,724	43	1,500
पुद्दुचेरी	96	92	2,801
पंजाब	10,458	178	24,089
राजस्थान	35,747	13,651	9,71,498
सिक्किम #	1	0	0
तमिलनाडु #	3	0	0
तेलंगाना #	5	0	0
त्रिपुरा **	19	893	5,71,783
उत्तर प्रदेश	90,573	67,516	1,01,81,864
उत्तराखंड	7,441	7,441	2,78,229
कुल	**3,20,647**	**1,61,723**	**24315,255**

नोट: कुछ राज्यों ने पहले से मौजूद डेटा या पहले से लागू इसी तरह के कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कारणों से योजना को लागू नहीं किया है। सिक्किम, तेलंगाना और तमिलनाडु ने कुछ गांवों के साथ केवल प्रायोगिक चरण में भाग लिया है, लेकिन पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण इसे जारी नहीं रखने का विकल्प चुना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड ने अभी तक योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल और केरल ने सूचित किया है कि ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के एक भाग के रूप में आवासीय संपत्तियों के अधिकारों के रिकार्ड पहले से मौजूद है। पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण ओडिशा और असम सीमित संख्या में गांवों में सर्वेक्षण कर रहे हैं। झारखंड में यह योजना फिलहाल रोक दी गई है। दिल्ली में 31 गांवों में योजना को लागू किया गया है लेकिन संपत्ति कार्ड अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक 2

स्वामित्व योजना' के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4077 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

धुले और नासिक में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान और संपत्ति कार्डों का विवरण

ज़िला	ड्रोन उड़ानपूरी करने वाले ग्रांव (	संपत्ति कार्डों का विवरण	
		गांवों की संख्या	तैयार किये गये संपत्ति कार्डों की संख्या
धुले	409	24	3,725
नासिक	1,431	738	1,01,979

अनुलग्नक 3

'स्वामित्व योजना' के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4077 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत आईईसी और एसपीएमयू के लिए राज्यों को जारी की गई धनराशि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल (रुपये में)
आंध्र प्रदेश	26,70,000
अरुणाचल प्रदेश	16,54,250
असम	1,16,99,750
छत्तीसगढ	13,14,500
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	2,19,750
गुजरात	33,36,641
हरियाणा	21,61,270
हिमाचल प्रदेश	41,15,250
कर्नाटक	7,75,125
केरल	3,84,375
लद्दाख	30,375
मध्य प्रदेश	92,77,500
महाराष्ट्र	10,52,500
मिजोरम	2,77,750
ओडिशा	11,50,000
पंजाब	67,84,500
राजस्थान	61,40,000

त्रिपुरा	3,87,000
उत्तर प्रदेश	1,44,75,000
उत्तराखंड	15,10,000